

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 384 का उत्तर

मुंबई में वसई से दिवा के बीच नई रेल लाइन

384. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मुम्बई मण्डल के अंतर्गत वसई से दिवा के बीच नई रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा; और
- (ग) उक्त कार्य में तेजी लाने में आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

मुंबई में वसई से दिवा के बीच नई रेल लाइन के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे के अतारांकित प्रश्न सं. 384 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग) वसई से दिवा पहले ही दोहरी बड़ी लाइन वाला एक मौजूदा खंड है। समानांतर संरेखण पर पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारे का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके अलावा, नायगांव और जुचन्द्र (5.73 किमी) के बीच वसई बाइपास लाइन (दोहरी लाइन) का निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। भविष्य की मांग के अनुसार उपनगरीय गलियारों का आगे विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है। इसके अलावा, पनवेल-विरार नए उपनगरीय गलियारे पर भी मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के एक भाग के रूप में ₹7,184 करोड़ की लागत पर महाराष्ट्र सरकार के साथ 50:50 लागत भागीदारी आधार पर विचार किया गया है।

उपनगरीय गलियारों पर भीड़भाड़ से बचने और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित 10 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ करोड़ में)
1	पांचवीं और छठी लाइन सीएसटीएम-कुर्ला (17.5 किमी)	891
2	छठी लाइन मुंबई सेंट्रल-बोरीवली (30 किमी)	919
3	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (29.6 किमी)	2782
4	ऐरोली-कलवा (एलिवेटेड) उपनगरीय कॉरिडोर लिंक (3.3 किमी)	476
5	विरार-दहानु रोड की तीसरी और चौथी लाइन (64 किमी) का चौहरीकरण	3587
6	हार्बर लाइन गोरेगांव-बोरीवली का विस्तार (7 किमी)	826
7	पांचवीं और छठी लाइन बोरीवली-विरार (26 किमी)	2184
8	कल्याण-आसनगांव के बीच चौथी लाइन (32 किमी)	1759
9	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (14.05 किमी)	1510
10	कल्याण यार्ड-मेन लाइन और उपनगरीय लाइन का पृथक्करण	866

इन सभी एमयूटीपी परियोजनाओं को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच लागत भागीदारी के आधार पर 50:50 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार मार्च 2022-23 तक प्रतिबद्धता के अनुसार समय पर अपेक्षित धनराशि प्रदान नहीं कर रही थी,

जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2023 से एमयूटीपी-IIIए परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण शुरू कर दिया है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानान्तरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, राज्य बिजली कंपनियों द्वारा पारेषण लाइन के कार्यों को पूरा करना जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जो रेल मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर हैं। ये सभी कारक परियोजनाओं को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं। अतः, इस स्थिति में परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।
